DATE 12.02.2026 TIME 11.30 AM PERIOD 3

subject family law

source of hindu law

ancient		modern	
a	shruti 4 vedas	a	judicial decision
b	smirit	b	legislation
c	digest and commentaries	c	justice equal and good concern
d	customs		

a SHRUTI

The term **Shruti** is derived from the Sanskrit word *"Shru"*, which means **"to hear."** Shruti literally means **"that which is heard."**

In Hindu Law, **Shruti** is considered the **primary and paramount source** of law. It is believed to contain the divine revelations that were heard by ancient sages (Rishis) from God and passed down orally from generation to generation.

Shruti mainly consists of the **Vedas**, which are:

- Rigveda
- Yajurveda
- Samaveda
- Atharvaveda

Each Veda is further divided into:

1. Samhitas
2. Brahmanas
3. Aranyakas
4. Upanishads

Since Shruti is regarded as divine and eternal, it holds the **highest authority** in the hierarchy of Hindu law sources. All other sources, such as Smriti (that which is remembered), customs, and judicial decisions, must conform to Shruti.

Corrected Version of Your Sentence:

"The term Shruti is derived from the word 'Shru', which means 'to hear'. It is considered to be the primary and paramount source of Hindu Law."

Smriti (स्मृति)

The term **Smriti** is derived from the Sanskrit word *"Smri"*, which means **"to remember."** Smriti literally means **"that which is remembered."**

In Hindu Law, **Smriti** is considered the **second important source** after Shruti. While Shruti is believed to be divine revelation, Smriti is based on the **traditions, teachings, and interpretations** given by ancient sages. It explains and elaborates the principles contained in the Vedas.

Main Smritis:

- Manusmriti
- Yajnavalkya Smriti
- Narada Smriti

Among these, **Manusmriti** is considered the oldest and most important.

Importance in Hindu Law:

- Smriti provides detailed rules regarding **marriage, inheritance, property, duties, and punishments**.
- When there is no clear rule in Shruti, Smriti is followed.
- If there is a conflict between Shruti and Smriti, **Shruti prevails**.

Short Exam Definition (5 Marks):

"Smriti is the second important source of Hindu Law. It means 'that which is remembered' and consists of rules and regulations written by ancient sages based on the teachings of the Vedas."

LLB (बैचलर ऑफ लॉज़) के द्वितीय सेमेस्टर में "**हिंदू विधि के स्रोत**" (**Sources of Hindu Law)** के अंतर्गत '**स्मृति**' **(Smriti)** एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।

कानूनी संदर्भ में स्मृति के बारे में मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

1. **स्मृति का अर्थ** (**Meaning of Smriti)**

- 'स्मृति' शब्द संस्कृत की 'स्मृ' धातु से बना है, जिसका अर्थ है "**याद किया हुआ**"।
- इन्हें ऋषियों द्वारा वेदों (श्रुति) के ज्ञान को याद करके और अपनी बुद्धि से संकलित करके लिखा गया था।
- जहाँ श्रुति को 'ईश्वरीय' माना जाता है, वहीं स्मृति को '**मानव निर्मित**' माना जाता है।

2. स्मृतियों का वर्गीकरण (Classification)

स्मृतियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है:

- **धर्मसूत्र (Dharmasutras):** ये गद्य (Prose) में लिखे गए हैं (जैसे- गौतम, बौधायन, आपस्तम्ब धर्मसूत्र)।
- **धर्मशास्त्र (Dharmashastras):** ये पद्य या श्लोकों (Poetry) में लिखे गए हैं।

3. प्रमुख स्मृतियाँ (Main Smritis)

कानूनी इतिहास में तीन स्मृतियाँ सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं:

- **मनुस्मृति (Manusmriti):** यह सबसे प्राचीन और आधारभूत स्मृति है। इसमें ऋण, उत्तराधिकार, विवाह और दंड जैसे 18 विधिक विषयों का वर्णन है।
- **याज्ञवल्क्य स्मृति (Yajnavalkya Smriti):** यह मनुस्मृति की तुलना में अधिक व्यवस्थित और संक्षिप्त है। आधुनिक हिंदू कानून के कई सिद्धांत इसी पर आधारित हैं।
- **नारद स्मृति (Narada Smriti):** यह मुख्य रूप से व्यवहार (Civil Law) और अदालती प्रक्रिया पर केंद्रित है।

4. स्मृति के तीन भाग (Three Parts of Smriti Rules)

स्मृतियों में कानून को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

1. **आचार (Achara):** सामाजिक और नैतिक व्यवहार के नियम (जैसे- विवाह)।
2. **व्यवहार (Vyavahara):** नागरिक और आपराधिक कानून (जैसे- संपत्ति विवाद)।
3. **प्रायश्चित (Prayaschit):** गलत कार्यों के लिए दंड या धार्मिक शुद्धि।

5. आधुनिक महत्व

यद्यपि आज हिंदू कानून संहिताबद्ध (Codified) हो चुका है, लेकिन उत्तराधिकार, विवाह और गोद लेने जैसे विषयों में स्मृतियों के सिद्धांत आज भी हिंदू विवाह अधिनियम (1955) और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) के मूल आधार के रूप में कार्य करते हैं।

LLB द्वितीय सेमेस्टर के लिए **मनुस्मृति** और **याज्ञवल्क्य स्मृति** के बीच मुख्य अंतर और नोट्स नीचे दिए गए हैं:

मनुस्मृति

और

याज्ञवल्क्य स्मृति

में तुलनात्मक अंतर

आधार	**मनुस्मृति** (Manusmriti)	**याज्ञवल्क्य स्मृति** (Yajnavalkya Smriti)
काल (Period)	यह सबसे प्राचीन स्मृति है (लगभग 200 ई.पू. से 200 ईस्वी).	यह मनुस्मृति के बाद की रचना है (लगभग 100 ईस्वी से 300 ईस्वी).
संरचना (Structure)	इसमें 12 अध्याय और लगभग 2,694 श्लोक हैं.	यह अधिक संक्षिप्त है, इसमें 3 अध्याय और केवल 1,010 श्लोक हैं.
विभाजन	विषयों का विभाजन व्यवस्थित नहीं है, धार्मिक और कानूनी नियम मिले हुए हैं.	इसे स्पष्ट रूप से 3 भागों में बांटा गया है: आचार, व्यवहार और प्रायश्चित.
राजा की शक्ति	राजा को 'दैवीय उत्पत्ति' (Divine Right) का प्रतीक माना गया है.	राजा को कानून के अधीन माना गया है, न कि उससे ऊपर.

स्त्रियों का स्थान	तुलनात्मक रूप से अधिक रूढ़िवादी है.	स्त्रियों के प्रति अधिक उदार है; उन्हें संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया है.
कानूनी प्रक्रिया	इसमें प्रक्रियात्मक कानून (Procedural Law) पर कम जोर दिया गया है.	इसमें साक्ष्य (Evidence) और अदालती प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन है.

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स (Exam Notes)

1. **मनुस्मृति का महत्व**: इसे 'मानव धर्मशास्त्र' भी कहा जाता है। यह हिंदू कानून का मूल स्तंभ है। इसमें ऋण, उत्तराधिकार और दंड जैसे 18 शीर्षकों (Titles of Law) का वर्णन है.
2. **याज्ञवल्क्य स्मृति**

की विशेषता: यह अपनी स्पष्टता और संक्षिप्तता के लिए जानी जाती है। प्रसिद्ध टीका '**मिताक्षरा**' (**विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित**) इसी स्मृति पर आधारित है, जो आज भी भारत के अधिकांश हिस्सों में उत्तराधिकार कानून का आधार है.

3. **स्मृति के प्रमुख लेखक**: याज्ञवल्क्य ने 20 स्मृति-कारों की सूची दी है, जिनमें अत्रि, विष्णु, हारीत, उशनास, अंगिरा, यम, आपस्तम्ब, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप और वशिष्ठ शामिल हैं.

Meaning of Digest and Commentaries in Hindu Law

In Hindu Law, **Digest and Commentaries** are considered important sources after Shruti and Smriti. They explain, interpret, and clarify the rules given in the Smritis.

---

1 Commentaries (**टीकाएँ**)

Commentaries are explanations written by learned scholars on Smriti texts to remove doubts and clarify meanings.

- They interpret difficult verses.

- They adapt ancient rules to changing social conditions.
- Courts have relied on them in deciding cases.

Important Commentaries:

- Mitakshara – Written by Vijnaneshwara on Yajnavalkya Smriti.
- Dayabhaga – Written by Jimutavahana.

These two schools (Mitakshara and Dayabhaga) became the foundation of Hindu law in different parts of India.

2️⃣ Digest (**निबंध**)

A **Digest** is a compilation or summary of rules collected from various Smritis and commentaries.

- It gathers opinions of different scholars.
- It compares and reconciles conflicting views.
- It presents the law in a systematic manner.

In simple words:

👉 **Commentary = Explanation of one Smriti**
👉 **Digest = Collection and summary of many Smritis and commentaries**

हिंदू विधि (Hindu Law) के विकास में **भाष्य** (**Commentaries**) और **निबंध** (**Digests**) का बहुत बड़ा महत्व है। सरल शब्दों में इनका अर्थ नीचे दिया गया है:

1. भाष्य (**Commentaries**)

- **अर्थ**: जब किसी विशेष **स्मृति** (जैसे मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति) की व्याख्या करने के लिए उस पर विस्तृत टीका लिखी गई, तो उसे 'भाष्य' कहा गया। [5.1]
- **उद्देश्य**: स्मृतियों की भाषा कठिन और संक्षिप्त थी। भाष्यकारों ने उनके अर्थ को सरल बनाया और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उनकी नई व्याख्या की। [5.1]
- **उदाहरण**:
    - **मिताक्षरा** (**Mitakshara**): यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर **विज्ञानेश्वर** द्वारा लिखा गया सबसे प्रसिद्ध भाष्य है। [5.1]

- **मनुभाष्य**: मेधातिथि द्वारा मनुस्मृति पर लिखी गई टीका।

2. निबंध (Digests)

- **अर्थ**: जब किसी एक स्मृति को आधार बनाने के बजाय, **कई स्मृतियों** से अलग-अलग विषयों को इकट्ठा करके एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा गया, तो उसे 'निबंध' कहा गया। [5.1]
- **उद्देश्य**: निबंधों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्मृतियों के बीच के विरोधाभासों (Contradictions) को दूर करना और एक सर्वसम्मत नियम बनाना था। [5.1]
- **उदाहरण**:
  - **दायभाग (Dayabhaga):** यह **जीमूतवाहन** द्वारा रचित एक अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध है, जो मुख्य रूप से उत्तराधिकार के नियमों पर केंद्रित है। [5.1]
  - **वीरमित्रोदय**: मित्र मिश्र द्वारा रचित।

भाष्य और निबंध में मुख्य अंतर

आधार	**भाष्य (Commentaries)**	**निबंध (Digests)**
आधार	यह किसी **एक विशेष स्मृति** पर आधारित होता है।	यह **अनेक स्मृतियों** का सार या संकलन होता है।
कार्य	यह मूल ग्रंथ (स्मृति) की व्याख्या करता है।	यह विभिन्न ग्रंथों के नियमों में सामंजस्य बिठाता है।
स्वतंत्रता	यह मूल पाठ (Original Text) से बंधा होता है।	यह लेखक के अपने दृष्टिकोण से अधिक स्वतंत्र होता है।

महत्व: आज भी भारत में हिंदू कानून के दो मुख्य संप्रदाय (Schools) – **मिताक्षरा** और **दायभाग** – इन्हीं भाष्यों और निबंधों की देन हैं। [5.1]

---

modern sources of hindu law.

📘 **Modern Sources of Hindu Law (English)**

Modern sources of Hindu Law are those sources which developed during and after British rule in India. These sources have modified and codified traditional Hindu law.

1. Judicial Decisions (Precedents)

Judicial decisions are one of the most important modern sources of Hindu law. Under the principle of **stare decisis**, the decisions of higher courts are binding on lower courts.

The decisions of:

- Supreme Court of India
- High Courts of India

have greatly contributed to the development and interpretation of Hindu law.

Example: Courts have interpreted customs, marriage laws, succession rights, etc.

---

2. Legislation (Statutory Law)

Legislation is the most important modern source. After independence, Hindu law was codified and reformed by Parliament.

Major Acts include:

- Hindu Marriage Act
- Hindu Succession Act
- Hindu Minority and Guardianship Act
- Hindu Adoptions and Maintenance Act

These Acts brought uniformity and removed many old discriminatory practices.

---

3. Justice, Equity and Good Conscience

When there is no rule in Shruti, Smriti, Custom, or legislation, courts apply the principle of justice, equity, and good conscience.
This principle was introduced during British rule.

---

4. Custom

Custom continues to be a modern source if it is:

- Ancient
- Certain
- Reasonable
- Not opposed to public policy

Courts recognize customs if they are properly proved.

📕 हिन्दू विधि के आधुनिक स्रोत (Hindi)

हिन्दू विधि के आधुनिक स्रोत वे हैं जो ब्रिटिश शासन के बाद विकसित हुए और जिनसे हिन्दू कानून में संशोधन एवं संहिताकरण हुआ।

1. न्यायिक निर्णय (Judicial Decisions)

न्यायालयों के निर्णय आधुनिक हिन्दू विधि का महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
Stare Decisis के सिद्धांत के अनुसार उच्च न्यायालयों के निर्णय निम्न न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं।

- Supreme Court of India
- High Courts of India

इन न्यायालयों ने विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक, अभिभावकत्व आदि विषयों पर महत्वपूर्ण व्याख्या की है।

---

2. विधायन (Legislation)

स्वतंत्रता के बाद संसद ने हिन्दू कानून को संहिताबद्ध किया। प्रमुख अधिनियम:

- Hindu Marriage Act
- Hindu Succession Act
- Hindu Minority and Guardianship Act
- Hindu Adoptions and Maintenance Act

इन अधिनियमों ने समानता और सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया।

---

3. न्याय, समता और सद्विवेक (Justice, Equity and Good Conscience)

जहाँ कोई स्पष्ट नियम उपलब्ध नहीं होता, वहाँ न्यायालय न्याय, समता और सद्विवेक के सिद्धांत को लागू करते हैं।

---

4. प्रथा (Custom)

यदि कोई प्रथा:

- प्राचीन हो
- निश्चित हो
- उचित हो
- लोकनीति के विरुद्ध न हो

तो न्यायालय उसे मान्यता देते हैं।

📘 **Hindu Marriage Act, 1955 – English & Hindi (LLB 2nd Sem)**

📖 **In English**

The **Hindu Marriage Act, 1955** is a codified law enacted to regulate marriage among Hindus. It applies to Hindus, Buddhists, Jains, and Sikhs.

🔹 **Important Features:**

1️⃣ **Conditions of a Valid Marriage (Section 5)**

- Monogamy (no living spouse at the time of marriage)
- Sound mind
- Marriageable age: 21 years (male), 18 years (female)
- Parties not within prohibited relationship (unless custom permits)

2️⃣ **Restitution of Conjugal Rights (Section 9)**

If one spouse withdraws without reasonable cause, the other may seek court relief.

3️⃣ **Judicial Separation (Section 10)**

Court allows spouses to live separately without dissolving the marriage.

4️⃣ **Divorce (Section 13)**

Grounds include:

- Adultery
- Cruelty
- Desertion
- Conversion
- Mental disorder
- Communicable disease (earlier provision amended)
- Mutual consent (Section 13B)

5️⃣ **Maintenance & Alimony (Sections 24 & 25)**

Financial support during and after proceedings.

📘 हिंदी में

Hindu Marriage Act, 1955 (हिंदू विवाह अधिनियम, 1955) हिंदुओं के विवाह को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। यह हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख पर लागू होता है।

🔹 **मुख्य प्रावधान**:

1️⃣ **वैध विवाह की शर्तें (धारा 5)**

- एकपत्नी प्रथा (पति/पत्नी जीवित न हो)
- मानसिक रूप से स्वस्थ
- आयु: पुरुष 21 वर्ष, महिला 18 वर्ष
- निषिद्ध संबंध में विवाह नहीं (जब तक प्रथा अनुमति न दे)

2️⃣ **दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना (धारा 9)**

यदि कोई पति/पत्नी बिना उचित कारण अलग रहता है, तो दूसरा पक्ष न्यायालय जा सकता है।

3️⃣ **न्यायिक पृथक्करण (धारा 10)**

विवाह समाप्त नहीं होता, परंतु अलग रहने की अनुमति मिलती है।

4️⃣ **तलाक (धारा 13)**

तलाक के आधार:

- व्यभिचार
- क्रूरता
- परित्याग
- धर्म परिवर्तन
- मानसिक विकार

- आपसी सहमति (धारा 13B)

5️⃣ **भरण-पोषण (धारा 24, 25)**

कार्यवाही के दौरान और बाद में आर्थिक सहायता।

Hindu marriage act 1955.

📘 **Hindu Marriage Act (English)**

1. Introduction

The Hindu Marriage Act, 1955 was enacted to amend and codify the law relating to marriage among Hindus.
It came into force on **18 May 1955**.

It applies to:

- Hindus
- Buddhists
- Jains
- Sikhs

(Not applicable to Muslims, Christians, Parsis, and Jews.)

---

2. Objectives

- To codify Hindu marriage law
- To provide conditions for valid marriage
- To introduce divorce provisions
- To promote monogamy
- To protect rights of women

---

3. Conditions for Valid Marriage (Section 5)

A Hindu marriage is valid if:

1. Neither party has a living spouse (Monogamy)/**bigamy.**
2. Both parties are of sound mind
3. Groom must be 21 years, bride 18 years
4. Parties are not within prohibited degrees
5. Not sapindas of each other (unless custom permits)

---

case for bigamy.

"Priya V Suresh 1971" refers to the landmark Indian Supreme Court case **Smt. Priya Bala Ghosh vs. Suresh Chandra Ghosh**, decided on March 4, 1971. This case is a fundamental authority in Indian family law regarding the proof required for the offence of **bigamy** under Section 494 of the Indian Penal Code.

Key Rulings of the Case

- **Strict Proof of Marriage:** The Court ruled that for a conviction of bigamy, the prosecution must prove that the second marriage was performed with all the **essential religious rites** and ceremonies (such as *Homa* and *Saptapadi* for Hindu marriages).
- **Insufficiency of Admissions:** A crucial aspect of this judgment is that a mere **admission** by the accused that they have remarried is not sufficient for a conviction. The second marriage must be proven as a fact through evidence of its solemnisation.
- **Validity Requirement:** Under Section 17 of the Hindu Marriage Act, a second marriage is only void—and thus bigamous—if it would have been a valid marriage but for the existence of the first spouse. If essential ceremonies are missing, the "marriage" is not legally a marriage at all, meaning the charge of bigamy cannot stand.

Case Details

- **Parties:** Priya Bala Ghosh (Appellant) vs. Suresh Chandra Ghosh (Respondent).
- **Bench:** Justices C.A. Vaidyialingam and A.N. Ray.

- **Outcome:** The Supreme Court **upheld the acquittal** of the husband because the prosecution failed to prove that the essential ceremonies for the second marriage had been performed

---

यह मामला **श्रीमती प्रिया बाला घोष बनाम सुरेश चंद्र घोष (1971)** के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय कानून में **द्विविवाह (Bigamy)** के अपराध को साबित करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है।

मामले के मुख्य बिंदु:

- **अनिवार्य धार्मिक रस्में:** सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि द्विविवाह (IPC की धारा 494) के तहत दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि दूसरी शादी **पूरी कानूनी और धार्मिक रस्मों** (जैसे हिंदू विवाह में 'सप्तपदी' और 'होम') के साथ संपन्न हुई थी।
- **सिर्फ स्वीकारोक्ति काफी नहीं:** अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि पति या पत्नी केवल यह **स्वीकार** कर लेते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो सिर्फ इस बयान के आधार पर उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। दूसरी शादी का ठोस सबूत होना जरूरी है।
- **कानूनी वैधता:** हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के तहत, दूसरी शादी तभी शून्य और दंडनीय मानी जाती है जब वह कानूनी रूप से संपन्न हुई हो। यदि आवश्यक रस्में नहीं निभाई गईं, तो कानून की नजर में वह 'शादी' ही नहीं है।

मामले का परिणाम:

इस मामले में, आरोपी (पति) को **बरी** कर दिया गया था क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि दूसरी शादी के समय सभी आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान सही ढंग से किए गए थे।

---

case for mental stability.

📘 **Alka Sharma v. Avinash Chandra (1991)**

- **Legal Issue:**

Whether a husband can be convicted for bigamy without strict proof of valid performance of essential marriage ceremonies.

- Principle Laid Down:

The Court held that:

- For establishing bigamy, mere cohabitation or admission is not enough.
- The second marriage must be proved to have been solemnized with essential Hindu rites and ceremonies.
- If essential ceremonies like *Saptapadi* are not proved, the offence under Section 494 IPC is not made out.

Thus, strict proof of a valid second marriage is necessary.

- **Legal Position Under Law**

Under Section 5(i) of the Hindu Marriage Act:

A marriage is valid only if neither party has a living spouse at the time of marriage.

If violated:

- The marriage is void (Section 11)
- Punishable under Section 494 IPC

हिंदी में

Alka Sharma v. Avinash Chandra (1991)

- मुख्य प्रश्न:

क्या बिना विवाह की आवश्यक रस्मों के प्रमाण के, पति को द्विविवाह (Bigamy) का दोषी ठहराया जा सकता है?

🔹 **न्यायालय का निर्णय:**

न्यायालय ने कहा:

- केवल साथ रहना (cohabitation) या स्वीकारोक्ति पर्याप्त नहीं है।
- दूसरी शादी को वैध सिद्ध करने के लिए आवश्यक हिन्दू रीति-रिवाज (जैसे सप्तपदी) का प्रमाण आवश्यक है।
- यदि आवश्यक संस्कार सिद्ध नहीं होते, तो धारा 494 IPC के अंतर्गत अपराध सिद्ध नहीं होगा।

🔎 **Important for Exam**

This case supports the same principle as:

- Bhaurao Shankar Lokhande v. State of Maharashtra
- Kanwal Ram v. Himachal Pradesh Administration

---

age of the person in relation of marriage.

Maninder Kaur v. Major Singh

📘 **Court:**

Punjab and Haryana High Court (1972)

🔹 **Issue:**

Whether a marriage performed below the prescribed age under the **Hindu Marriage Act** is **void** or merely punishable?

🔹 **Legal Provision Involved:**

Section 5(iii) of the Hindu Marriage Act

- Groom: 21 years

- Bride: 18 years

(At that time, the prescribed age was lower; later amended.)

🔹 **Facts:**

- The marriage was performed when one of the parties had not attained the required minimum age.
- The question before the court was whether such a marriage becomes invalid.

🔹 **Judgment / Principle:**

The Court held:

1. Marriage in contravention of the prescribed age is **not void** under the Hindu Marriage Act.
2. Such marriage is **valid**, but punishable under Section 18 of the Act.
3. Age condition is **not included** under Sections 11 (void marriages) or 12 (voidable marriages).
4. Therefore, minority does not automatically invalidate the marriage.

🔹 **Important Legal Point (Exam Oriented):**

👉 Under Hindu Marriage Act, violation of age requirement does **not** make the marriage void.
👉 It only attracts **penalty**.

📕 हिंदी में

Maninder Kaur v. Major Singh (1972)

🔹 **मुख्य प्रश्न:**

क्या कम आयु में किया गया विवाह शून्य (Void) है?

🔹 **निर्णय:**

न्यायालय ने कहा:

- आयु संबंधी शर्त (धारा 5(iii)) का उल्लंघन विवाह को शून्य नहीं बनाता।
- ऐसा विवाह वैध रहेगा।
- केवल धारा 18 के तहत दंडनीय होगा।

🔎 **परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:**

✓ आयु की शर्त का उल्लंघन = विवाह वैध रहेगा
✓ परंतु दंड लागू होगा
✓ शून्य विवाह केवल धारा 11 में दिए गए मामलों में होता है

🟥 **Section 18 - Punishment for contravention of certain conditions**

Under the Hindu Marriage Act

Section 18 provides punishment if the conditions of **Section 5** are violated.

🔹 **Section 18(a) - Prohibited Relationship / Sapinda**

If marriage is solemnized:

- Within **prohibited degrees of relationship**, or
- Between **sapindas** (without valid custom),

👉 Punishment:

- **Simple imprisonment up to 1 month**, or
- **Fine up to ₹1,000**, or
- Both.

🔹 **Section 18(b) - Age Requirement (Section 5(iii))**

If marriage is solemnized in violation of the **minimum age condition**:

(Current age: Groom - 21 years, Bride - 18 years)

👉 Punishment:

- **Simple imprisonment up to 2 years**, or
- **Fine up to ₹1 lakh**, or
- Both.
  (As amended by later laws)

🔎 **Important Exam Points**

✓ Violation of age condition does **not make marriage void**.
✓ It only attracts punishment.
✓ Bigamy punishment is under Section 17 (read with IPC 494), not Section 18.

📕 हिंदी में

धारा 18 - शर्तों के उल्लंघन पर दंड

(हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955)

🔹 **(क) निषिद्ध संबंध / सपिंड विवाह**

- 1 माह तक साधारण कारावास
- या ₹1000 तक जुर्माना
- या दोनों

🔹 **(ख) आयु संबंधी शर्त का उल्लंघन**

- 2 वर्ष तक साधारण कारावास
- या ₹1,00,000 तक जुर्माना

- या दोनों

---

4. Ceremonies (Section 7)

Marriage must be solemnized according to customary rites and ceremonies. Saptapadi (seven steps) is essential in many cases.

---

5. Restitution of Conjugal Rights (Section 9)

If one spouse withdraws without reasonable cause, the other may file a petition for restitution.

---

6. Judicial Separation (Section 10)

Court permits spouses to live separately without dissolving marriage.

---

7. Divorce (Section 13)

Grounds for divorce include:

- Adultery
- Cruelty
- Desertion (2 years)
- Conversion
- Mental disorder
- Communicable disease (as amended)
- Renunciation
- Presumption of death

---

8. Void and Voidable Marriage

Void Marriage (Section 11):

- Bigamy
- Prohibited relationship

Voidable Marriage (Section 12):

- Impotency
- Fraud
- Force
- Pregnancy by another person

---

9. Maintenance and Alimony (Sections 24 & 25)

Court may grant:

- Interim maintenance
- Permanent alimony

---

10. Importance

It brought major reforms such as:

- Abolition of polygamy
- Legal recognition of divorce
- Protection of women's rights

📘 Restitution of Conjugal Rights Under Section 9 of the Hindu Marriage Act

---

🔹 Meaning

Restitution of Conjugal Rights means the **restoration of marital rights** when one spouse withdraws from the society of the other without reasonable excuse.

🔹 Section 9 – Provision

If:

- Either the husband or wife
- Has withdrawn from the society of the other
- Without reasonable cause

👉 The aggrieved party may file a petition in the District Court.
👉 The court may pass a decree for restitution of conjugal rights.

🔹 Essential Conditions

1. Valid marriage must exist.
2. One spouse must have withdrawn.
3. Withdrawal must be without reasonable excuse.
4. Petition must be filed in competent court.

🔹 Burden of Proof

The burden lies on the person who has withdrawn to prove reasonable excuse.

🔹 Effect of Decree

- Court orders the spouse to resume cohabitation.
- If decree is not obeyed for **1 year**, it becomes a ground for divorce under Section 13(1A).

🔹 Important Case Laws

1. **T. Sareetha v. T. Venkata Subbaiah**
   Held Section 9 unconstitutional (violation of privacy).

2. **Saroj Rani v. Sudarshan Kumar Chadha**
   Supreme Court upheld constitutional validity of Section 9.

🔎 **Exam Points**

✓ It is a matrimonial remedy.
✓ It does not dissolve marriage.
✓ Non-compliance for 1 year → Ground for divorce.

📕 हिंदी में

दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना (धारा 9)

यदि पति या पत्नी बिना उचित कारण के दूसरे से अलग हो जाए, तो पीड़ित पक्ष न्यायालय में वाद दायर कर सकता है।

आवश्यक तत्व:

- वैध विवाह
- बिना उचित कारण अलगाव
- न्यायालय की डिक्री

प्रभाव:

- साथ रहने का आदेश
- 1 वर्ष तक पालन न होने पर तलाक का आधार

🟥 Judicial Separation Under Section 10 of the Hindu Marriage Act

---

🔹 **Meaning**

Judicial Separation means a **legal separation** of husband and wife by a court decree, without dissolving the marriage.

The marriage continues to exist, but spouses are not bound to live together.

🔹 Grounds (Section 10)

After the 1976 amendment, the grounds for Judicial Separation are the same as for divorce under Section 13, such as:

- Adultery
- Cruelty
- Desertion
- Conversion
- Mental disorder
- Renunciation
- Presumption of death

🔹 Essential Points

1. Valid marriage must exist.
2. Petition must be filed in District Court.
3. Court must be satisfied about the grounds.

🔹 Effect of Judicial Separation

✓ Spouses are not required to cohabit.
✓ Marriage is not dissolved.
✓ Rights and duties remain, except cohabitation.
✓ If no resumption of cohabitation for 1 year → Ground for divorce under Section 13(1A).

🔹 Difference Between Judicial Separation and Divorce

Judicial Separation	Divorce
Marriage continues	Marriage dissolved
Temporary relief	Permanent termination
Possible reconciliation	No marital status remains

- **Important Case**

Bipinchandra Jaisingbhai Shah v. Prabhavati
Laid down principles relating to desertion, which apply to judicial separation and divorce.

हिंदी में

न्यायिक पृथक्करण (धारा 10)

न्यायालय द्वारा पति-पत्नी को अलग रहने की अनुमति देना, बिना विवाह समाप्त किए।

आधार:

- व्यभिचार
- क्रूरता
- परित्याग
- धर्म परिवर्तन
- मानसिक विकार

प्रभाव:

✓ विवाह समाप्त नहीं होता

✓ साथ रहने की बाध्यता समाप्त

✓ 1 वर्ष तक साथ न रहने पर तलाक का आधार

🟥 Nullity of Marriage Under the Hindu Marriage Act

Nullity of marriage means a **declaration by the court that the marriage is null and void**.

It is of two types:

🔹 1. Void Marriage (Section 11)

A marriage is **void from the beginning (void ab initio)** if it violates:

1. **Bigamy** - Either party has a living spouse at the time of marriage.
2. **Prohibited degrees of relationship** (unless custom permits).
3. **Sapinda relationship** (unless custom permits).

👉 Such marriage is treated as if it never existed.

👉 Either party may file a petition for declaration of nullity.

🔹 2. Voidable Marriage (Section 12)

A marriage is valid until annulled by court. It becomes void only after a decree.

Grounds:

1. Impotency
2. Unsoundness of mind
3. Consent obtained by fraud
4. Consent obtained by force
5. Wife pregnant by another person at the time of marriage

👉 Petition must be filed within prescribed time.

🔎 **Important Difference**

Void Marriage	Voidable Marriage
Automatically invalid	Valid until annulled
No legal existence	Valid unless challenged
Covered under Section 11	Covered under Section 12

🔹 **Legitimacy of Children**

Under Section 16 of the Act:
Children of void and voidable marriages are **legitimate**, though property rights are limited to parents' property.

📕 हिंदी में

विवाह की शून्यता (Nullity of Marriage)

🔹 **शून्य विवाह (धारा 11)**

- द्विविवाह
- निषिद्ध संबंध
- सपिंड संबंध

👉 विवाह प्रारंभ से ही अमान्य माना जाएगा।

🔹 **शून्यकरणीय विवाह (धारा 12)**

- नपुंसकता
- मानसिक अस्वस्थता

- धोखा
- बल प्रयोग
- विवाह के समय पत्नी का किसी अन्य से गर्भवती होना

👉 न्यायालय की डिक्री के बाद ही अमान्य होगा।

🔎 परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

✓ Void = प्रारंभ से अमान्य

✓ Voidable = न्यायालय के आदेश से अमान्य

✓ बच्चों की वैधता सुरक्षित

🟥 Divorce Under Section 13 of the Hindu Marriage Act

🔹 Meaning

Divorce means the **legal dissolution of marriage** by a decree of the court.
After divorce, the marital relationship permanently ends.

🔹 Grounds for Divorce (Section 13)

A husband or wife may seek divorce on the following grounds:

1. **Adultery**
2. **Cruelty**
3. **Desertion** (for 2 years)
4. **Conversion** to another religion
5. **Unsoundness of mind / mental disorder**
6. **Venereal disease** (as amended)

7. **Renunciation of the world**
8. **Presumption of death** (not heard for 7 years)

- **Additional Grounds Available to Wife (Section 13(2))**
  - Husband guilty of rape, sodomy, or bestiality
  - Husband has another wife living
  - Non-resumption of cohabitation after maintenance decree
  - Marriage before 15 years of age (repudiation before 18 years)

- **Divorce by Mutual Consent (Section 13B)**

Conditions:

1. Husband and wife living separately for at least 1 year
2. Both agree to dissolve the marriage
3. Petition filed jointly

Court grants divorce after satisfaction.

- **Divorce after Judicial Separation / Restitution**

If no resumption of cohabitation for **1 year** after decree of:

- Judicial separation
- Restitution of conjugal rights

It becomes a ground for divorce (Section 13(1A)).

- **Important Case**

Naveen Kohli v. Neelu Kohli

Supreme Court recommended inclusion of irretrievable breakdown of marriage as a ground for divorce.

📕 हिंदी में

तलाक (धारा 13)

तलाक विवाह का न्यायालय द्वारा स्थायी रूप से समाप्त होना है।

तलाक के आधार:

- व्यभिचार
- क्रूरता
- 2 वर्ष का परित्याग
- धर्म परिवर्तन
- मानसिक विकार
- संन्यास
- 7 वर्ष तक जीवित न होने की सूचना

आपसी सहमति से तलाक (धारा 13B):

- 1 वर्ष से अलग रहना
- दोनों की सहमति

🔎 परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

✓ तलाक विवाह को पूर्णतः समाप्त कर देता है।

✓ आपसी सहमति से तलाक अलग प्रावधान है।

✓ 1 वर्ष का अलगाव महत्वपूर्ण है।

🟥 Legitimacy of Children Under Section 16 of the Hindu Marriage Act

---

🔹 Meaning

Legitimacy means the **legal status of a child born from a valid marriage**, giving the child rights in the property of parents.

🔹 Section 16 – Legitimacy of Children of Void and Voidable Marriages

Even if a marriage is:

- **Void** (Section 11), or
- **Voidable** (Section 12),

👉 The children born from such marriage are considered **legitimate**.

🔹 Important Points

1. Child remains legitimate even if marriage is declared null by court.
2. This provision protects innocent children.
3. Legitimacy applies whether marriage is declared before or after the child's birth.

🔹 Property Rights

✓ Child can inherit property of **parents only**.

❌ Child cannot claim property rights in joint family ancestral property of other relatives (as per earlier interpretation).

🔹 **Important Case**

Revanasiddappa v. Mallikarjun

Supreme Court held that children born from void marriages should not suffer and should get rights in parents' property.

📕 हिंदी में

संतान की वैधता (धारा 16)

यदि विवाह:

- शून्य (Void), या
- शून्यकरणीय (Voidable)

हो, तब भी उससे उत्पन्न संतान **वैध (Legitimate)** मानी जाएगी।

मुख्य बिंदु

✓ संतान निर्दोष है, इसलिए उसके अधिकार सुरक्षित हैं।
✓ माता-पिता की संपत्ति में अधिकार है।
❌ अन्य रिश्तेदारों की पैतृक संपत्ति में अधिकार सीमित है।

🔎 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण

👉 धारा 16 बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुधार का प्रावधान है।

🟥 Adoption (दत्तक ग्रहण) Under the Hindu Adoptions and Maintenance Act

---

🔹 Meaning

Adoption means **legally taking a child as one's own child**, giving him/her the same rights as a natural-born child.

📘 Essentials of Valid Adoption

🔹 1. Capacity of Male Hindu to Adopt (Section 7)

- Must be major and of sound mind.
- If married, consent of wife is necessary (unless she has renounced the world, converted, or declared of unsound mind).

🔹 2. Capacity of Female Hindu to Adopt (Section 8)

- Must be major and of sound mind.
- If unmarried, widow, divorced, or husband disqualified, she can adopt.

🔹 3. Persons Who May Give in Adoption (Section 9)

- Father
- Mother
- Guardian (with court's permission)

🔹 4. Persons Who May Be Adopted (Section 10)

- Must be Hindu
- Must not already be adopted
- Must be unmarried (unless custom permits)

- Must be below 15 years (unless custom permits)

🔹 **5. Other Conditions (Section 11)**

- If adopting a son, adoptive parent must not already have a living son/son's son.
- If adopting a daughter, must not already have a living daughter.
- If male adopts a female child, he must be at least 21 years older than the child (and vice versa).

📘 **Effects of Adoption (Section 12)**

✓ Adopted child is deemed the child of adoptive parents.
✓ All rights and duties transfer to adoptive family.
✓ Ties with biological family are severed (except marriage restrictions).

🔹 **Important Case**

Laxmi Singh v. State of Rajasthan
Adoption must be strictly proved; mere claim is not sufficient.

📕 हिंदी में

दत्तक ग्रहण

दत्तक ग्रहण का अर्थ है किसी बच्चे को विधिक रूप से अपनी संतान बनाना।

आवश्यक शर्तें:

✓ दत्तक लेने वाले की क्षमता
✓ दत्तक देने वाले की वैधता
✓ बच्चे की पात्रता
✓ धारा 11 की शर्तों का पालन

दत्तक का प्रभाव:

✓ बच्चा विधिक संतान माना जाएगा

✓ संपत्ति में अधिकार मिलेगा

✓ जन्म परिवार से संबंध समाप्त

🔎 परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

👉 दत्तक लेने के बाद बच्चा प्राकृतिक संतान के समान अधिकार प्राप्त करता है।

👉 आवश्यक शर्तों का पालन न होने पर दत्तक अमान्य होगा।

🟥 Hindu Minority and Guardianship Act

The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 was enacted to **amend and codify the law relating to minority and guardianship among Hindus**.
It is supplementary to the Guardians and Wards Act.

🔹 1. Application of the Act (Section 2)

Applies to:

- Hindus
- Buddhists
- Jains
- Sikhs

🔹 2. Meaning of Minor (Section 4)

A **minor** is a person who has not completed **18 years of age**.

🔹 **3. Natural Guardians (Section 6)**

(a) For a boy or unmarried girl:

- **Father**, and after him, **Mother**

(b) For illegitimate child:

- **Mother**, and after her, **Father**

(c) For married minor girl:

- **Husband**

👉 However, custody of a child below 5 years is ordinarily with the mother.

🔹 **4. Powers of Natural Guardian (Section 8)**

- Guardian can do acts necessary for benefit of minor.
- Cannot transfer minor's immovable property without court permission.
- Any unauthorized transfer is voidable.

🔹 **5. Testamentary Guardian (Section 9)**

A Hindu father or mother may appoint a guardian by **will**.

🔹 **6. Welfare of Minor (Section 13)**

Welfare of the minor is the paramount consideration.
No guardian shall be appointed if it is not in the interest of the minor.

🔹 **Important Case**

Githa Hariharan v. Reserve Bank of India

Supreme Court held:

- The word “after” in Section 6 does not mean after the lifetime of father.
- Mother can also act as natural guardian during father’s lifetime if father is absent or indifferent.

📕 हिंदी में

हिन्दू अल्पसंख्यक एवं अभिभावक अधिनियम, 1956

उद्देश्य:

अल्पवयस्क (Minor) और अभिभावक (Guardian) संबंधी कानून को संहिताबद्ध करना।

🔹 मुख्य प्रावधान

✓ 18 वर्ष से कम आयु = अल्पवयस्क
✓ पिता प्राकृतिक अभिभावक, उसके बाद माता
✓ 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की अभिरक्षा सामान्यतः माता को
✓ संपत्ति बेचने हेतु न्यायालय की अनुमति आवश्यक
✓ बच्चे का हित सर्वोपरि सिद्धांत

🔎 परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

👉 Welfare of minor is paramount.
👉 माता भी प्राकृतिक अभिभावक हो सकती है।
👉 बिना न्यायालय अनुमति संपत्ति हस्तांतरण अमान्य हो सकता है।

📕 Law of Maintenance Under the Hindu Adoptions and Maintenance Act

The Act codifies the law relating to **maintenance of wife, children, aged parents and dependants** among Hindus.

🔹 **Meaning of Maintenance (Section 3)**

"Maintenance" includes:

- Food
- Clothing
- Residence
- Education
- Medical attendance and treatment
- In case of unmarried daughter – reasonable marriage expenses

---

🔹 **1. Maintenance of Wife (Section 18)**

A Hindu wife is entitled to be maintained by her husband during her lifetime.

She can claim separate residence without losing maintenance if:

- Husband is guilty of cruelty
- Husband deserts her
- Husband has another wife
- Husband converts religion
- Any other justifiable cause

❌ Wife is not entitled if she is unchaste or converts religion.

🔹 **2. Maintenance of Widowed Daughter-in-law (Section 19)**

She can claim maintenance from her father-in-law if:

- She cannot maintain herself
- She has no property
- Husband's estate is insufficient

🔹 3. Maintenance of Children and Aged Parents (Section 20)

A Hindu is bound to maintain:

- Legitimate or illegitimate minor children
- Unmarried daughter
- Aged or infirm parents

🔹 4. Maintenance of Dependants (Section 21-22)

After death of a Hindu, dependants can claim maintenance from his estate.

Dependants include:

- Widow
- Minor children
- Aged parents
- Unmarried daughters

🔹 5. Amount of Maintenance (Section 23)

Court considers:

- Position and status of parties
- Reasonable wants of claimant
- Value of property
- Income of both parties

🔹 6. Effect of Transfer of Property (Section 25)

If property is transferred to defeat maintenance rights, it can be challenged.

- **Important Case**

Chaturbhuj v. Sita Bai

Court held that maintenance depends on husband's capacity and wife's needs.

हिंदी में

भरण-पोषण का कानून

(हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956)

भरण-पोषण में शामिल:

✓ भोजन

✓ वस्त्र

✓ आवास

✓ शिक्षा

✓ चिकित्सा

✓ अविवाहित पुत्री के विवाह खर्च

पत्नी का अधिकार (धारा 18)

पति जीवनभर पत्नी का भरण-पोषण करेगा।

माता-पिता और संतान (धारा 20)

✓ नाबालिग संतान

✓ अविवाहित पुत्री

✓ वृद्ध माता-पिता

आश्रितों का अधिकार (धारा 21-22)

मृतक हिन्दू की संपत्ति से आश्रितों को भरण-पोषण।

🔎 परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

👉 भरण-पोषण सामाजिक न्याय का प्रावधान है।

👉 पत्नी, संतान, माता-पिता को अधिकार।

👉 अदालत आय और स्थिति देखकर राशि तय करती है।

📘 Law of Succession under the Hindu Succession Act

The Hindu Succession Act, 1956 deals with **inheritance and succession of property among Hindus**.

🔹 1. Devolution of Interest in Coparcenary Property (Section 6)

- Originally, only **male coparceners** had rights by birth in Mitakshara coparcenary property.
- After the **2005 Amendment**, **daughters are also coparceners by birth**, equal to sons.
- Daughter has:
  - ✓ Same rights
  - ✓ Same liabilities
  - ✓ Right to demand partition

Important Case:

Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma
Supreme Court held that daughter becomes coparcener **by birth**, whether father is alive or not on 9 Sept 2005.

🔹 2. General Rules of Succession in Case of Male Hindu (Section 8)

If a male Hindu dies intestate (without will), property devolves in this order:

✓ **Class I Heirs:**

- Son
- Daughter
- Widow
- Mother
- Son of predeceased son/daughter, etc.

✓ **Class II Heirs:**

If no Class I heirs exist, then Class II heirs inherit.

✓ **Agnates:**

If no Class I & II heirs.

✓ **Cognates:**

If no agnates.

🔹 **3. General Rules of Succession in Case of Female Hindu (Section 15)**

If a female Hindu dies intestate, property devolves:

1. Sons and daughters (including children of predeceased children) and husband
2. Heirs of husband
3. Mother and father
4. Heirs of father
5. Heirs of mother

👉 Property inherited from parents goes back to parental heirs if no children.

🔹 **4. Testamentary Succession (Section 30)**

A Hindu may dispose of property by **Will**.

- Applies to separate/self-acquired property.
- After 2005 amendment, coparcenary interest can also be disposed by will.

हिंदी में

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

- **धारा 6 - सहभोजी (Coparcenary) संपत्ति**
  - 2005 संशोधन के बाद पुत्री को पुत्र के समान अधिकार।
  - जन्म से सहभोजी का दर्जा।

- **धारा 8 - पुरुष हिन्दू की मृत्यु पर उत्तराधिकार**
  - वर्ग । वारिस
  - वर्ग ॥ वारिस
  - अग्नेट
  - कॉग्नेट

- **धारा 15 - स्त्री हिन्दू की मृत्यु पर उत्तराधिकार**
  - पुत्र, पुत्री, पति
  - पति के वारिस
  - माता-पिता
  - पिता के वारिस
  - माता के वारिस

🔹 धारा 30 - वसीयत द्वारा उत्तराधिकार

- हिन्दू अपनी संपत्ति वसीयत द्वारा दे सकता है।

🔎 परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

✓ 2005 संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण।

✓ पुत्री = सहभोजी (Coparcener)

✓ पुरुष और स्त्री के उत्तराधिकार नियम अलग हैं।

📕 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindi)

1. परिचय

Hindu Marriage Act हिन्दुओं के विवाह संबंधी कानून को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए बनाया गया।
यह 18 मई 1955 से लागू हुआ।

यह लागू होता है:

- हिन्दू
- बौद्ध
- जैन
- सिख

---

2. उद्देश्य

- विवाह कानून का संहिताकरण

- एक विवाह प्रथा (Monogamy)
- तलाक की व्यवस्था
- स्त्रियों के अधिकारों की सुरक्षा

---

3. वैध विवाह की शर्तें (धारा 5)

- किसी पक्ष का जीवित जीवनसाथी न हो
- दोनों स्वस्थ मस्तिष्क के हों
- वर 21 वर्ष, वधू 18 वर्ष
- निषिद्ध संबंध में न हों
- सपिंड संबंध में न हों

---

4. विवाह संस्कार (धारा 7)

विवाह प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार होना चाहिए।
सप्तपदी को कई मामलों में आवश्यक माना गया है।

---

5. दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना (धारा 9)

यदि कोई पक्ष बिना उचित कारण अलग हो जाए।

---

6. न्यायिक पृथक्करण (धारा 10)

पति-पत्नी अलग रह सकते हैं, पर विवाह समाप्त नहीं होता।

---

7. तलाक (धारा 13)

आधार:

- व्यभिचार
- क्रूरता
- परित्याग (2 वर्ष)
- धर्म परिवर्तन
- मानसिक विकार
- संन्यास
- मृत्यु की संभावना

हिंदू विधि (Hindu Law) में **मिताक्षरा** और **दायभाग** के बीच का अंतर परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। यहाँ इनका तुलनात्मक विवरण और नोट्स दिए गए हैं:

मिताक्षरा और दायभाग में मुख्य अंतर

आधार	**मिताक्षरा** (Mitakshara)	**दायभाग** (Dayabhaga)
रचयिता	इसके रचयिता **विज्ञानेश्वर** हैं।	इसके रचयिता **जीमूतवाहन** हैं।
आधार	यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित एक **भाष्य** है।	यह कई स्मृतियों का सार (निबंध) है।

क्षेत्र (Region)	यह असम और बंगाल को छोड़कर **पूरे भारत** में मान्य है।	यह मुख्य रूप से **बंगाल और असम** में मान्य है।
संपत्ति का अधिकार	पुत्र को पिता की संपत्ति में अधिकार **जन्म लेते ही** मिल जाता है।	पुत्र को अधिकार पिता की **मृत्यु के बाद** ही मिलता है।
स्वामित्व	पुत्र पिता के जीवनकाल में भी संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकता है।	पिता के जीवित रहते पुत्र बंटवारे की मांग नहीं कर सकता।
उत्तरजीविता का नियम	यहाँ '**उत्तरजीविता का सिद्धांत**' (Doctrine of Survivorship) लागू होता है।	यहाँ '**उत्तराधिकार का सिद्धांत**' (Doctrine of Inheritance) लागू होता है।
सहदायिकी (Coparcenary)	इसमें केवल पुरुष ही सहदायिकी का हिस्सा होते थे (2005 के संशोधन से पहले)।	इसमें केवल पिता की मृत्यु के बाद ही सहदायिकी बनती है।

विस्तृत नोट्स (Detailed Notes)

1. **मिताक्षरा संप्रदाय** (Mitakshara School)

- **जन्मजात अधिकार**: इस विचारधारा के अनुसार, एक बालक जैसे ही परिवार में जन्म लेता है, वह अपने पिता, दादा और परदादा की पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदार बन जाता है।
- **अविभाजित परिवार**: इसमें परिवार की संपत्ति का हिस्सा तब तक निश्चित नहीं होता जब तक कि बंटवारा (Partition) न हो जाए।
- **शाखाएं**: मिताक्षरा की पांच उप-शाखाएं हैं: बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र (बंबई), द्रविड़ (मद्रास) और पंजाब शाखा।

2. दायभाग संप्रदाय (Dayabhaga School)

- **मृत्यु उपरांत अधिकार**: जब तक पिता जीवित है, वह संपत्ति का पूर्ण स्वामी है। पुत्र का उस पर कोई कानूनी हक नहीं होता।
- **निश्चित हिस्सा**: इसमें प्रत्येक हिस्सेदार का भाग पहले से ही काल्पनिक रूप से निश्चित होता है।
- **स्त्रियों का अधिकार**: इसमें विधवा को संतान न होने पर भी अपने पति की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार मिताक्षरा की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से दिया गया था।

याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बात:

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के बाद अब मिताक्षरा और दायभाग के बीच का अंतर काफी कम हो गया है, क्योंकि अब बेटियों को भी बेटों के बराबर पैतृक संपत्ति में जन्मजात अधिकार (Coparcener) दे दिया गया है।

Custom (रीति-रिवाज) in Hindu Law

Custom means a rule of conduct which has been **continuously and uniformly observed for a long time**, and which has obtained the force of law in a particular community, tribe, family, or locality.

In Hindu Law, **Custom is an important source of law.** In some cases, a valid custom can even override the written texts (Smriti), if it is ancient and certain.

✅ **Definition**

"Custom is a rule which, having been observed continuously and peacefully for a long time, obtains the force of law."

📌 **Essentials of a Valid Custom**

For a custom to be legally recognized, it must be:

1. **Ancient** – Followed since time immemorial.
2. **Certain** – Clear and not vague.
3. **Reasonable** – Not opposed to justice, equity, or good conscience.

4. **Continuous** – Followed without interruption.
5. **Not opposed to public policy or statutory law.**

⚖️ Importance in Hindu Law

- Custom plays a very important role in matters like **marriage, adoption, inheritance, and joint family system.**
- Courts in India have recognized custom as a valid source of Hindu law.
- Under the Hindu Marriage Act and Hindu Succession Act, certain customs are recognized if they fulfill legal conditions.

Short Exam Answer (5 Marks)

"Custom is a rule of conduct which has been followed continuously and has acquired the force of law. It is an important source of Hindu law and may override the written law if it is ancient, certain, reasonable, and continuous."

विधि शास्त्र और हिंदू कानून में **'रूढ़ि' या 'प्रथा' (Custom)** कानून का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन स्रोत है। [1]

रूढ़ि (Custom) का अर्थ

रूढ़ि से तात्पर्य उन नियमों या व्यवहारों से है जो किसी विशेष परिवार, वर्ग या क्षेत्र में **बहुत लंबे समय से** लगातार चले आ रहे हैं। [1] जब कोई व्यवहार समाज में इतनी गहराई से समा जाता है कि उसे कानून के समान मान्यता मिल जाती है, तो उसे 'रूढ़ि' कहते हैं। [2]

एक वैध रूढ़ि (Valid Custom) की आवश्यक शर्तें

कानून की दृष्टि से किसी भी प्रथा को वैध होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है: [2]

1. **प्राचीनता (Antiquity):** प्रथा बहुत पुरानी होनी चाहिए। इसका कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन इसे "स्मरण शक्ति से परे" (Immemorial) माना जाना चाहिए। [2]
2. **निरंतरता (Continuity):** वह प्रथा बिना किसी रोक-टोक के लगातार चलती आ रही हो। [2]

3. **निश्चितता** (**Certainty**): प्रथा स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। [2]
4. **तार्किकता** (**Reasonableness**): प्रथा तर्कसंगत होनी चाहिए और न्याय या नैतिकता के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। [2]
5. **लोक नीति के विरुद्ध न हो** (**Not against Public Policy**): वह राज्य के कानूनों या सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। [2]
6. **अनिवार्यता** (**Observance as a Right**): लोग उस प्रथा का पालन किसी डर से नहीं, बल्कि अपना अधिकार या कर्तव्य समझकर करते हों। [1]

रूढ़ियों के प्रकार

- **स्थानीय रूढ़ि** (**Local Custom**): जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मान्य हो। [1]
- **वर्ग रूढ़ि** (**Class Custom**): जो किसी विशेष जाति या समुदाय में मान्य हो। [1]
- **पारिवारिक रूढ़ि** (**Family Custom**): जो केवल एक विशेष परिवार में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही हो। [1]

महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत

हिंदू कानून में एक प्रसिद्ध सिद्धांत है: "**एक वैध रूढ़ि लिखित कानून** (**Text**) **से अधिक शक्तिशाली होती है।**" [1] इसका अर्थ है कि यदि कोई प्राचीन प्रथा किसी पुराने धार्मिक पाठ के विरुद्ध भी है, तो अदालत उस प्रथा को ही मान्यता देगी।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भी कुछ रूढ़ियों को विशेष संरक्षण दिया गया है, जैसे कुछ समुदायों में होने वाले विशिष्ट विवाह संस्कार। [3]

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की **धारा 5** के अनुसार, एक वैध विवाह के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें और **सपिण्ड** (**Sapinda**) संबंधों का निषेध महत्वपूर्ण है।

1. हिंदू विवाह की अनिवार्य शर्तें (धारा 5)

एक विवाह तभी वैध माना जाता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों: [5.1]

- **एकविवाह (Monogamy):** विवाह के समय किसी भी पक्ष का पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए।
- **मानसिक स्वस्थता**: कोई भी पक्ष पागल या गंभीर मानसिक विकार से ग्रस्त नहीं होना चाहिए ताकि वह वैध सहमति दे सके।
- **न्यूनतम आयु**: दूल्हे की आयु **21 वर्ष** और दुल्हन की आयु **18 वर्ष** पूर्ण होनी चाहिए। [5.1]
- **निषिद्ध नातेदारी (Prohibited Relationship):** दोनों पक्ष एक-दूसरे के निषिद्ध नातेदारी की डिग्री के भीतर नहीं होने चाहिए (जब तक कि उनकी रूढ़ि इसकी अनुमति न दे)।
- **सपिण्ड संबंध (Sapinda Relationship):** दोनों पक्ष एक-दूसरे के सपिण्ड नहीं होने चाहिए।

---

2. सपिण्ड (Sapinda) संबंध क्या है?

'सपिण्ड' का अर्थ है वे लोग जो एक ही '**पिण्ड**' (शरीर के अंश या पूर्वज) से जुड़े हों। [5.1]

सपिण्ड की सीमाएँ (धारा 3-f):
कानून के अनुसार, आप निम्नलिखित सीमाओं के भीतर विवाह नहीं कर सकते:

1. **पिता की ओर से**: ऊपर की **5 पीढ़ियों** तक।
2. **माता की ओर से**: ऊपर की **3 पीढ़ियों** तक।

गणना में उस व्यक्ति को पहली पीढ़ी माना जाता है जिससे गिनती शुरू होती है। [5.1]

---

3. निषिद्ध नातेदारी की डिग्रियाँ (Degrees of Prohibited Relationship)

धारा 3(g) के तहत निम्नलिखित संबंधों में विवाह वर्जित है: [5.1]

- यदि एक दूसरे का वंशज (Descendant) हो (जैसे पिता-पुत्री)।

- यदि एक दूसरे के वंशज की पत्नी या पति रहा हो (जैसे पुत्रवधू या दामाद)।
- भाई-बहन, चाचा-भतीजी, बुआ-भतीजा, या भाई-बहन की संतानें।

अपवाद (Exception)

यदि किसी समुदाय या जनजाति की '**रूढ़ि**' (Custom) ऐसे विवाह की अनुमति देती है (जैसे दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मामा-भांजी का विवाह), तो वह विवाह धारा 5 के तहत वैध माना जाएगा। [5.1]

उल्लंघन का परिणाम

- **शून्य विवाह** (Void Marriage): यदि सपिण्ड या निषिद्ध नातेदारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो विवाह शुरुआत से ही **अमान्य** (Zero) माना जाता है। [5.1]
- **दंड**: धारा 18 के तहत, इन शर्तों को तोड़ने पर जुर्माना या साधारण कारावास की सजा हो सकती है।

---

full course completed.